[Shri Govinda Menon]

the statutory duty of the Commission to conduct the elections.

श्री भोगेन्द्र भा (जयनगर): उपाध्यक्ष महोदय, नियम 222 के ग्रधीन में निम्नलिखित प्रस्ताव संसद् सदस्यों एवं संतद् के विशेषाधि-कार-हनन के ग्रभियोग सम्बन्धी पटना के हिन्दी 'ग्रायंवत्तं' के विरुद्ध पेश करता हं:

दिनाँक 19-4-1970 के भ्रपने सम्पादकीय में दैनिक 'भ्रायंबर्त्त' ने लोक-सभा में.....

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY: This could be taken up after the lunch hour. Are you creating a precedent every day that we will not adjourn exactly at the lunch hour but will carry on for some more time?

MR. DEPUTY-SPEAKER: So long the practice has been to dispose of Call attention, Papers to be laid and other items, before lunch. Sometimes we spill over because questions drag on. But if it is the pleasure of the House, we will adjourn now and take it up after lunch.

SOME HON. MEMBERS: Yes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We adjourn for lunch now.

13.15 hrs.

The lok Labha adjourned for Lurch till fifteen minutes past Fourteen of the Clock.

The Lok Subha re-assembled after Lunch at eighteen minutes past Fourteen of the Clock.

[Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour): Mr. Deputy-Speaker, I will not take more than one minute. There is disturbing news in some papers today that the Central Government is bringing in the PD Act for West Bengal through backdoor. That Act had been turned down on the national front and here in this House also. For this purrose the Central Intelligence have sent a team of CID officers who are planting

agents provocateur in Calcutta and thus an artificial atmosphere is created. Government must take this House into confidence and make a statement clarifying the position, and say whether they want to introduce the PD Act through the backdoor, hoodwinking the people. The PD Act had been turned down on the national front and in this forum also.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): The Assembly has been suspended; it is not dissolved. So, they cannot bring the PD Act through the backdoor.

14.20 hrs.

QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST THE EDITOR, "ARYAVRATA"

श्री मोगेन्द्र भा (जयनगर): उपाध्यक्ष महोदय, एतद्वारा मैं नियम 222 के ग्रधीन पटना के हिन्दी दैनिक 'ग्रायंवर्त' के विरुद्ध संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हनन का ग्रभियोग ला रहा है। दिनांक 19-4-70 के अपने सम्पादकीय में दैनिक ग्रायांवर्त ने लोक सभा में संस्कृत ग्रन्थों की बिक्री के प्रश्न पर कम्युनिस्ट सदस्यों की देश भक्ति तथा उनकी ईमानदारी पर गहरा आघात किया है। उसने यह अभियोग लगाया है कि कम्यूनिस्ट संसद सदस्य किसी अन्य देश को अपना "पितदेश" मानते हैं तथा नहीं चाहते हैं कि भारत में ऐसी चीजें सूरक्षित रहें जिन से भारत की प्राचीन विचार-धारा, परम्परायें, संस्कृति, सभ्यता, भादि की रक्षा हो सकती है। उस सम्पादक के सम्पादकीय का वह श्रंश साथ में संलग्न है, परन्तु उस सम्पादकीय के एक हिस्से को मैं सदन के सामने पढ रहा हं-

"लोक सभा में जनसंघी सदस्य श्री राम गोपाल शालवाले का यह रहस्योद्घाटन कम्यु-निस्ट संसद् सदस्यों को बहुत बुरा लगा कि सेख प्रब्दुला जब जम्मू-काश्मीर के प्रधान मंत्री थे उस समय उन्होंने बहां के कितने संस्कृत 201 Question of Priviege VAISAKHA 1, 1892 (SAKA) against the 'Aryavrata'

प्रन्यों को विदेशियों के हाथ बेच दिया था। इस पर हमें आक्ष्य नहीं होता। कम्युनिस्ट इस देश में जन्म लेने के बावजूद अपना पितृदेश किसी और देश को मानते हैं और उसी पितृ देश की संस्कृति उन्हें प्रिय है। इस लिए बे नहीं चाहते कि भारत में ऐसी चीजें सुरक्षित रहें जिनसे भारत की प्रचीन विचारधारा, परम्पराएं, संस्कृति, सभ्यता, आदि की रक्षा हो सकती है। इसलिए यदि शेख अब्दुला ने संस्कृत की अमूल्य पुस्तकें बेच दीं और उनके इस काम की आलोचना की गई तो कम्युनिस्टों को बुरा लगना स्वाभाविक है...

MR. DEPUTY SPEAKER: I might give you the information.

श्री भोगेन्द्र भाः उपाध्यक्ष महोदय. मैं सिर्फ इतनाही कहनाचाहता है कि इस पर घलोचना होती है तो उस पर मुक्ते एतराज नहीं था। लेकिन ग्रध्यक्ष महोदय को भी उस समय बूरा लगा और उन्होंने एक बार कहा भी कि व्यक्तिगत आरोप मत लगाइये। संसद सदस्यों की जो भी राय थी, वह उन्होंने यहां पर दी, गलत थी या सही थी. मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन उसको लेकर यह कहा जाना कि वे इस देश को अपनी मात्रभमि नहीं मानते हैं और इसी लिए प्राचीन संस्कृति की रक्षा नहीं होने देना चाहते हैं ऐसी बात कह कर संसद सदस्य की हैसियत से जो काम, हम यहां करते हैं, हमारे उस ग्रधिकार का हनन किया है। इस लिए मैं चाहता हं कि इस विषय को विशेषाधिकार समिति के सुपूर्व कर दिया जाय ।

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): I support it.

MR. DEPUTY-SPEAKER: On this we have written to the editor of this paper. Let us await the reply and then we shall see to it.

14.23 hrs.

## PAPERS LAID ON THE TABLE

Reports of C. S. I. R., and of School of Planning and Architecture and Notification under the U. G. C. Act

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (SHKI BHAKT DARSHAN): On behalf of Dr. V. K. R. V. Rao,

I beg to lay on the Table :---

- (1) (i) A copy each of the Audit Reports on the accounts of the Council of Scientific and Industrial Research for the years 1966-67 and 1967-68.
  - (ii) A statement showing reasons for delay in laying the above Audit Reports. [Placed in Library. See No. LT—3294/70]
- (2) A copy of the Annual Report of the School of Planning and Architecture, New Delhi, for the year 1968-69. [Placed in Library. See No. LT-32°5/70]
- (3) A copy of the University Grants Commission (Teems and Conditions of Service of employees) Amendment Rules, 1970 (Hindi and English versions) published in Notification No. G. S. R. 508 in Gazette of India dated the 28th March, 1970, under sub-section (3) of section 25 of the University Grants Commission Act, 1956. [Placed in Library. See No. LT-3296/70]

## Notifications under the All-India Services Act and the Central Industrial Security Force Act

SHRI BHAKT DARSHAN: As authorised by Shri Vidya Charan Shukia, I beg to lay on the Table:

- A copy each of the following Notification under sub-section (2) of section 3 of the All India Services Act. 1951:
  - (i) The Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Second Amendment Regula-